कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय, मुंगेर–811202

E-Mail- eenhlakhisarai-bih@gov.in Mob. No. 9470001314

पत्रांक 661 (अनु०) मुंगेर / दिनांक 02-08-2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल
लखीसराय मुख्यालय, मुंगेर।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः–शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत NH-333A बरबीघा–शेखपुरा– सिकन्दरा–जमुई–झाझा– बाँका– पंजवारा झारखंड बोर्डर तक (0.00–198.45 कि0मी0) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 142.7368 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा अनुपालन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक– 789 दिनांक– 26.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रस्ताव के Online आवेदन में उठाये गये त्रुटियों का निम्नवत निराकरण कर समर्पित की जाती है।

Sl.	Querries	Compliance
i	The authorization letter at PART-1; A-3 (xvii) is not specific. It should be singularly issued in the name of applicant. Similarly, entries B-2.3 & B-24 may be comprehended.	N/A
ii	The KML file of the proposed forest marked for diversion is erroneous. It needs to be corrected.	KML File attached.
iii	Cross-section layout map of the proposed Road is missing.	uploaded
iv	Certified copy of area calculation by the concerned DFOs.	Attached
v	Cost Benefit analysis is not correct. It may be rectified.	Rectified cost Benefit analysis attached.
vi	NOCs from concerned parent departments like railways, transmission lines which the proposed road is intended to pass in forest is mandatory before issuance of Stage-I approval.	N/A
vii	Proposal involves forest area more than 100 ha., therefore SIR of State Nodal Officer-FC is required.	Approval given
viii	Compensatory Afforestation (CA) has been proposed over Degraded Forest Land (DFL) which needs to be proposed over Non-Forest Land (NFL) for state government proposals.	Exemption for providing non forest land has been requested to CAMPA vide this office letter no. 640(we) dated-25.07.2025.
ix	Information related to employment generation at entry E(ii) & (iii) may be corrected.	This is very important and connecting to inter states and heavy populated area.Hence ,this project will be generate employment in future.
x	Entries at 5 of PART-II may be highlighted clearly.	Yes.
xi	Site Inspection Reports of all the inspecting authorities (e.g. DFOs, CFs etc.) must be signed with date over the name of inspecting authority.	Site inspection has been done by DFO Jamui vide letter no. 1038 dated. 13.04.2023

सूचनार्थ सादर समर्पित।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल,
लखीसराय मु0–मुंगेर।

ज्ञापांक– 661 (अनु.) दिनांकः– 2.8.25

प्रतिलिपि–वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

02/08/25

कार्यपालक अभियन्ता
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल,
लखीसराय मु0–मुंगेर।

ज्ञापांक– 661 (अनु.) दिनांकः–02.08.25

प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

अनु0–यथोक्त।

02/08/25

कार्यपालक अभियन्ता
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल,
लखीसराय मु0–मुंगेर।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय, मुंगेर–811202

E-Mail- eenhlakhisarai-bih@gov.in Mob. No. 9470001314

पत्रांक 640(अनु0) मुंगेर / दिनांक 25-07-2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल
लखीसराय मुख्यालय, मुंगेर।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह– नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

विषयः–वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 के तहत राज्य अन्तर्गत पथ निर्माण परियोजना NH-333A शेखपुरा–सिकंदरा–जमुई–झाझा–बांका–पंजवारा झारखंड बोर्डर तक (0–198.45 कि0मी0) पथ के लिए 142.7368 हे0 वन भूमि अपयोजन के बदले समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने में छूट प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः–1) भवदीय पत्रांक–738 दिनांक–04.10.2024

2) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, नई दिल्ली का अधिसूचना दिनांक–20.09.2024

3) NH Act 1956 Act No. 48 of 1956 दिनांक–11.09.1956

4) सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–2858 (अनु0) दिनांक–17.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि विषयांकित कार्य का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 142.7368 हे0 वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है, परन्तु उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों में भारत सरकार के परियोजनाओं में समतुल्य गैर वन भूमि देने के लिए छूट दी गयी है। उक्त कार्य (NH-333A) भारत सरकार की परियोजना है, जिसकी स्वीकृति एवं कार्य का भुगतान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि NH-333A परियोजना का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में गैर वन भूमि उपलब्ध कराने से छूट देने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
25/07/25
कार्यपालक अभियन्ता
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल,
लखीसराय मु0–मुंगेर।

ज्ञापांक– 640(अनु0) दिनांकः–25-07-2025

प्रतिलिपि–वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

अनु0–यथोक्त।

25/07/25
कार्यपालक अभियन्ता
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल,
लखीसराय मु0–मुंगेर।

ज्ञापांक– 640 (अनु0) दिनांकः– 25-07-2025

प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

अनु0–यथोक्त।

25/07/25

कार्यपालक अभियन्ता
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल,
लखीसराय मु0–मुंगेर।

बिहार सरकार

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्याः–एन0एच0–24/विविध–01–28/2018 • 2858 (अनु०) दिनांकः– 17.10.2024

प्रेषक,

डॉ0 संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी,
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय— **वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 के तहत राज्य अन्तर्गत पथ निर्माण परियोजनाओं में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

प्रसंग—1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) बिहार, पटना का पत्रांक–738 दिनांक–04.10.2024.

2) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, नई दिल्ली का अधिसूचना दिनांक–20.09.2024.

3) NH Act 1956 Act No.-48 of 1956 **दिनांक–11.09.1956**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 2023 (संशोधन) (01.12.2023 से प्रभावी) लागू होने के फलस्वरूप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत सभी महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ, क्षतिपूरक वनीकरण के लिए वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के क्रम में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अबतक लम्बित स्थिति में है।

इस बीच पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 2023 में दिनांक–20.09.2024 को संशोधन किया गया है। जिसके आलोक में केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित परियोजनाओं में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 के तहत अपयोजित होने वाले वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराने से छूट प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार NH Rule 1956 सह पठित S.R.O. 1182 दिनांक–04.04.1957 (छायाप्रति संलग्न) के अनुरूप कार्यकारी एजेंसी है।

NH Act 1956 (Act No.-48 of 1956) के कंडिका–5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारत सरकार द्वारा राज्य अन्तर्गत पड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च पथों/राष्ट्रीय उच्च पथों के कतिपय पथांशों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु सुपुर्द की गई है (बिहार राज्य हेतु संसूचित अधिसूचना की अद्यतन प्रति संलग्न)। राज्य सरकार को सुपुर्द की गयी राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण परियोजनाओं/अनुरक्षण पर होने वाले व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा की जाती है एवं इसका भुगतान भी क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय उच्च पथ की योजनाओं की परिकल्पना निर्माण, अनुरक्षण आदि कार्यो के कार्यान्वियन हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को निश्चित दर से Agency Charge का भुगतान किया जाता है। (Agency Charge से संबंधित परिपत्र की प्रति संलग्न) ।

अतः अनुरोध है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं, जिनका कार्यान्वियन MoRTH द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, उन सभी परियोजनाओं में गैर वन भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा संसूचित संशोधन दिनांक–20.09.2024 के आलोक में अपवादात्मक परिस्थिति के अनुरूप वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराने से छूट प्रदान किया जाय तथा Stage-1 स्वीकृति हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करते हुये निर्धारित समय–सीमा में स्वीकृति संसूचित करने की कृपा की जाय। जिन मामलों में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, राँची द्वारा स्टेज–1 की स्वीकृति समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के शर्त्त के साथ दी गई है, उन मामलों में इस शर्त्त को विलोपित करने हेतु पुनः क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्ताव उपस्थापित करते हुए संशोधित स्वीकृति प्रंाप्त करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

17.10.24

(डॉ0 संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)

ज्ञापांक– 2858 दिनांक– 17-10-2024

प्रतिलिपि –अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह– नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

17.10.24

(डॉ0 संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)

ज्ञापांक– 2858 दिनांक– 17-10-2024

प्रतिलिपि –मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

17.10.24

(डॉ0 संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)

५०२५

[illegible]

[signature]
17/10/24

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092024-257289
CG-DL-E-20092024-257289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024/भाद्र 29, 1946
No. 540] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024/BHADRA 29, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 582(अ).— वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2024 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे और पांचवें परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह भी कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवक्रमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है, जिसका विस्तार, मामला दर मामला आधार पर, केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों या केन्द्रीय सार्वजनिक

527

क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के मामले में, प्रस्तावित क्षेत्र के दुगुने क्षेत्र के बराबर हो।

3. उक्त नियमों की अनुसूची-II में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 2 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्तावों पर ही यह विधान अनुज्ञात है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 3 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(यह वितरण मामला-दर-मामला आधार पर कैप्टिव कोयला ब्लॉक्स के लिए राज्य के सार्वजनिक के उपक्रम और मामला-दर-मामला आधार पर केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के मामले में है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एफसी-11/111/2024-एफसी]

रमेश कुमार पांडेय, वन महानिरीक्षक

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 869(अ), तारीख 29 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2024

G.S.R. 582(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, namely: —

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1), for the third, fourth, and fifth proviso, the following proviso, shall be substituted, namely : —

"Provided also in exceptional circumstances when the suitable land required for compensatory afforestation under this sub-rule is not available, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of the Central Government agencies or Central Public Sector Undertakings or captive coal blocks of State Public Sector Undertakings on a case to case basis".

3. In Schedule-II to the said rules, in the table, —

(i) The entries against serial number 2, under the brackets and words "*(This dispensation is allowed to certain proposals of Central Government and State Government or Union territory Administration only.)" shall be omitted;*

(ii) The entries against serial number 3, under the brackets and words "*(This dispensation is in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis and Central Government Agencies/Central Public Sector Undertakings on case to case basis involving no acquisition of non-forest land)*" shall be omitted.

[F. No. FC- 11/111/2024-FC]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 869(E), dated the 29th November, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS
(P&M Section)

Transport Bhawan,
1, Parliament Street,
New Delhi-110 001

No. 11014/7/2013-P& M **Dated 14th August, 2013.**

To

1. The Principal Secretaries/Secretaries of States/Union Territories, Public Works Department (dealing with National Highways, other Centrally Sponsored Schemes and State Schemes)
2. The Engineer-in-Chief and Chief Engineers of Public Works Department of State/Union Territories (dealing with National Highways, other Centrally Sponsored Schemes and State Schemes).
3. The Director General (Border Roads), Seema Sadak Bhawan, Ring Road, New Delhi.

Subject: Centages for NH works to be implemented on EPC Mode through State PWD,s and BRO.

Sir,

I am directed to say that this Ministry, vide letter no. RW/NH-37010/4/2010/PIC dated 26.11.2012 has decided that, all National Highways projects would be implemented on EPC Mode based on Model Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract Document. The model EPC Contract Document provides for provision of Authority's Engineer for supervision of the works, maintenance of the project reach for two years after completion of civil works and price escalation during construction as well as maintenance period.

2. The various centages being proposed for the NH works at the time of preparation of estimates has been reviewed by the Ministry. With the approval of Competent Authority, it has been decided that following centages shall be proposed in the estimates/technical proposals for NH works to be executed on EPC mode projects under NH(O), NHDP-IV etc. to be implemented through State PWD's/ BRO (Not NHAI):

Cost of work (Rs. in crore)	upto 25	>25-upto 50	>50 -upto 100	>100
Contingency	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
Agency Charges	3%	3%	3%	3%
Quality Control	1%	0.75%	0.5%	0.25%
Road Safety	1%	0.75%	0.5%	0.25%
Supervision	6%	5%	4%	3%

3. The contingency charges will be admissible only on the estimated cost of the work. The other centage charges i.e agency charges, quality control, road safety and supervision charges should be added individually to the estimated cost of work which includes 2.8% contingency charges. It is requested that necessary instruction may be issued to all concerned in your Department to follow the procedure, for preparing the estimates. For the works to be implemented on item rate contract basis, the centages shall be as per the existing guidelines of the Ministry.

4. While working out the provision for price escalation, the timelines for completion of civil construction works as circulated vide Ministry's letter no. RW/NH-33044/18/2012-S&R(R) dated 16.07.2012 shall be adhered to.

5. This issues with the concurrence of the Finance Division vide their U.O. No.1404/TF-II/13 dated 13.08.2013.

Yours faithfully,

(Surajit Dutta)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No.:23753990

Copy to:

1. All Technical Officers of the Ministry
2. All ROs and ELOs, MoRT&H
3. PS to Hon'ble Minister (RT&H)
4. Sr. PPS to Secretary (RT&H)
5. PPS to DG (RD) & SS
6. PPS to AS & FA
7. PPS to ADG-1, PPS to ADG-2, PPS to ADG-3

(v) **Transportation:**

Transportation and movement charges for the samples, equipment, staff etc. in respect of the quality control of the work project.

(vi) **Credit for the salvage/book value of the equipment, materials/implement etc.:**

The credit for the residual value of the usable equipment, implements, materials, etc. which were originally charged to a particular book, determined as per prevailing practice shall be given to the work estimates on completion of the work.

(vii) **Expenditure incurred on training of field level staff.**

The objective of the training being
(a) Familiarization with the specifications.
(b) Knowledge of correct sampling procedure
(c) Learning testing methodology.

(viii) **Expenditure on experiment work**

For effective location specific improvement in materials and techniques

(ix) **Purchase of computers:**

The expenditure on purchase of computers up to a limit, not exceeding 20% of the amount provided of quality control under a project can be allowed. However, this amount would be subject to ceiling of Rs. 5 Lacs.

1.2.2 Accounting:

The details of the account under this account head shall be maintained separately as is being done in case of the main work, contingencies and Project Specific temporary contractual staff and the expenditure shall be debitable on actual basis.

1.3 Project Specific temporary contractual staff

This provision is meant to cover expenditure on non-supervisory staff (whether regular or casual) employed specifically for execution of work such as personnel engaged on traffic regulation, road diversion, maintenance, watch & ward of stores and field office, collection and handling of samples of materials and survey work etc.

1.4 Agency Charges

The agency charges to be paid to the executing agency are meant to cover the following items broadly:

1.4.1 Pay and allowances of supervisory staff engaged in construction including TA/DA.

1.4.2 Office expenses of the PWD establishment including cost of stationery, Photostat, telephone bills, electric bills rentals and fax charges etc.

1.4.3 Purchase of petrol/diesel/gas oils and lubricants for cars/ jeeps and other transport/inspection vehicles for supervisory staff.

1.4.4 Expenditure on regular staff required for Preliminary Investigator work viz. subsoil/ bearing capacity investigation and topographic/ hydraulic survey etc. in preparation of project designs/estimates.

****

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252913
CG-DL-E-14032024-252913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1270] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945
No. 1270] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

का.आ. 1335(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे कार्यों को करने के लिए तत्समय प्रभावी नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"4	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2सी, सं. 19 [किमी 143.200 से किमी 207.200 (छपरा-हाजीपुर) **और किमी 128.713 से किमी 131.500 (उ. प्र. / बिहार सीमा से रावलगंज बाइपास खंड)** तक खंड को छोड़कर], सं. 28बी, सं. 30ए, सं. 80 [किमी 1.430 से किमी 190.000 (मोकामा-मुंगेर-मिर्जाचौकी	बिहार राज्य सरकार

	खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 81, सं. 82 [किमी 95.000 से किमी 149.020 (बिहारशरीफ – बरबिगहा-मोकामा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 98 [बिहार राज्य में प्रस्तावित हरिहरगंज बाइपास के भाग को छोड़कर], सं. 99, सं. 101, सं. 103, सं. 104, सं 105, सं. 106, सं. 110, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 333 [रारा-33 (नई सं.) पर बरियारपुर से प्रारंभ होकर खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई, चकई को जोड़ने वाला राजमार्ग], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327 विस्तार [चै. 00.000 किमी से चै. 93.983 किमी (गलगलिया – बहादुरगंज – अररिया खंड) और परसरमा – बनगांव – महिशी खंड (29.60 किमी) तक खंड को छोड़कर], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 131ए [पश्चिम बंगाल राज्य में मालदा से शुरू होने वाला, रतुआ और देवीपुर को जोड़ने वाला, रारा-31 पर आमदाबाद, मनिहारी, कटिहार को जोड़ने वाला और रारा-27 (नई सं.) पर पूर्णिया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग)], नई रारा सं. 120, नई रारा सं. 122ए, नई रारा सं. 122बी, नई रारा सं. 124सी, नई रारा सं. 131बी, नई रारा सं. 133, नई रारा सं. 133ई, नई रारा सं. 219, नई रारा सं. 227ए, नई रारा सं. 227एफ, नई रारा सं. 319ए, नई रारा सं. 322 (मुसरीघरारी के निकट रारा-122 के जंक्शन से बेला नवादा के निकट रारा-27 के जंक्शन तक का विस्तारित भाग), नई रारा सं. 327ए, नई रारा सं. 327एडी, नई रारा सं. 333ए, नई रारा सं. 333सी, नई रारा सं. 139डब्ल्यू [(बकरपुर से अरेराज खंड) तक को छोड़कर], नई रारा सं. 527ए [रहिका (पोखरौनी) – मधुबनी – रामपट्टी खंड और बिदेश्वर स्थान – लौफा – पश्चिमी कोसी नदी बांध के निकट भेजा खंड तक को छोड़कर], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 527ई, नई रारा सं. 727ए, नई रारा सं. 727एए और नई रारा सं. 727बी के उतने भाग जो बिहार राज्य में अवस्थित हैं।	

[फा. सं. एनएच-14013/12/2023-पी एंड एम(पार्ट)]

अभय जैन, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.-1060(अ), तारीख 05 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

S.O. 1335(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"4	So much of National Highways No.2C, No. 19 [excluding from Km. 143.200 to Km. 207.200 (Chhapara- Hajipur) **and Km. 128.713 to Km. 131.500 (UP/ Bihar border to Rawalganj Bypass section)]**, No. 28B, No.30A, No. 80 [excluding from km.1.430 to km.190.000 (Mokama-Munger-Mirzachowki section)], No.81, No.82 [excluding from Km. 95.000 to Km. 149.020 (Biharsharif-Barbigha-Mokama section)], No. 98 [excluding portion of proposed Hariharganj bypass in the state of Bihar)], No. 99, No. 101, No. 103, No. 104, No. 105, No. 106, No. 110, new National Highway number 333 [the highway starting from Bariyarpur on NH-33 (new number) connecting Kharagpur, Laxmipur, Jamui, Chakai], new National Highway number 327 Extension [excluding from Ch. 00.000 km to Ch. 93.983 km (Galgalia-Bhadurganj- Araria section) and Parsarma- Bangaon- Mahishi section (29.60 km)], new National Highway number 131A [the Highway starting from Malda, connecting Ratua and Debipur in the State of West Bengal, connecting Amdabad, Manihari, Katihar on NH31 and terminating at Purnia on NH-27 (new number)], new NH No. 120, new NH No. 122A, new NH No. 122B, new NH No 124C, new NH No 131B, new NH No. 133, new NH No 133E, new NH No. 219, new NH No. 227A, new NH No. 227F, new NH No. 319A, new NH No. 322 (Extended part from junction with NH-122 near Mushrigharari to junction with NH-27 near Bela Nawada) , new NH No. 327A, new NH No. 327AD, new NH No. 333A, new NH No 333C , new NH No. 139W [(excluding from Bakarpur to Areraj section], new NH No. 527A [excluding from Rahika (Pokhrauni)- Madhubani- Rampatti section and from Bideshwar asthan- Laufa- Bheja near West Kosi River Bandh section], new National Highway number 527E, new NH No. 727A, new NH No. 727AA and new NH No. 727B as are situated within the State of Bihar.	State Government of Bihar."

[F. No. NH-14013/12/2023-P&M(Pt.)]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1060 (E), dated the 5th March, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

का.आ. 1336(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदतुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज/लंबाई किमी में (3)
रारा-31 (पुराना रारा-19)	उ. प्र. / बिहार सीमा से रावलगंज बाइपास खंड (बिहार राज्य में)	किमी 128.713 से किमी 131.500

[फा. सं. एनएच-14013/12/2023-पी एंड एम(पार्ट)]

अभय जैन, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

S.O. 1336(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/ length in km (3)
NH-31 (old NH-19)	UP/ Bihar border to Rawalganj Bypass section (In the state of Bihar)	Km. 128.713 to Km. 131.500

[F. No. NH-14013/12/2023-P&M(Pt.)]

ABHAY JAIN, Dy. Secy

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

NOTIFICATION

PL-7 (4)/57-III | Dated the 4th April, 1957

S.R.O. 1182. In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, namely :

1. Short title—These rules may be called the National Highways Rules. 1957

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires

   (a) "Act" means the National Highways Act. 1956.

   (b) "approved work" means any original work on a national highway in respect of which the Central Government has accorded technical approval and financial sanction;

   (c) "completion report" means a report required to be furnished under rule 8;

   (d) **"executive agency" means —**

      (i) in the case of a Union Territory the Administrator thereof to whom the functions of the Central Government in relation to the execution of works pertaining to national highways are delegated under article 239 of the Constitution; and

      (ii) in any other case the State Government to which such functions are delegated under section 5 of the Act; and

   (e) "progress report" means a report required to be furnished under rule 7.

Detailed estimates of original works : A detailed estimate for the execution of any original work on a national highway shall be forwarded by the executive agency to the Central Governmnt in such form as the Central Government may require and that Government may accord technical approval and financial sanction to such estimate subject to any conditions it may think fit to impose. Unless authorised by the Central Government, no original work on any national highway shall be undertaken by the executive agency until technical approval and financial sanction have been accorded by that Government except in cases of emergency, such as flood, earthquake or any other force majeure which shall be immediately reported to the Central Government and the Audit Officer concerned, indicating the approximate amount of liability involved.

4. *Abstract of particulars of detailed estimate for maintenance of national highways :* (1) An abstract of the particulars of the detailed estimate for the maintenance of a national highway during each financial year shall be forwarded by the executive agency to the Central Government in such form as the Central Government may require not later than the 1st day of the month of May in that financial year.

Provided that the Central Government may, in any case of class of cases, require the executive agency to forward a detailed estimate or estimates for the maintenance of any national highway in such form as that Govenment may require.

(2) The Central Government may accord approval to the abstract or the detailed estimate or estimate submitted to it under this rule subject to any conditions it may think fit to impose.

Revised detailed estimate : When the expenditure upon any original work on a national highway to the detailed estimate of which the Central Government has accorded technical approval and financial sanction exceed, or is likely at any time to exceed, the amount of such estimate by more than ten per cent thereof or by a sum of twenty-five thousand rupees, whichever is less, the exectuive agency shall forward a revised detailed estimate for such work to the Central Government in such form as the Central Government may require, and the Central Government may accord technical approval and financial sanction to such estimate subject to any conditions it may think fit to impose.

Application for allotment of funds : An application for the allotment of funds for meeting expenditure on any original work on a national highway or on the maintenance of a national highway during any financial year shall be made by the executive agency to the Central Government in such form as that Government may require and the Central Government shall communicate its decision to the executive agency on such application as soon as possible after such application is received.

Monthly progress report : The executive agency shall furnish to the Central Government a monthly progress report on every approved work in such form as that Government may require.